प्रदेश में 24 देशों ने किया 50 हजार करोड़ का निवेश

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से बढ़ेगा एफडीआई

10 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश का लक्ष्य

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यूपी विदेशी निवेशकों का मनपसंद स्थान बन गया है। यहां 24 देशों ने 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। अगले साल जनवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस-23) से प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और बढ़ने की संभावना है। इससे प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य भी पूरा होगा।

अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग ने विदेशी निवेश को लेकर डेडिकेटेड हेल्पडेस्क बनाई है। पिछले पांच साल में 12 देशों से 26,371 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 39 परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित हो चुकी है। इससे 38 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रमुख निवेशक देशों में सिंगापुर, अमेरिका, जापान, यूके, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया शामिल हैं।

इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 के तहत जापान, कोरिया, फ्रांस, कनाडा, ताईवान, बेल्जियम, फिनलैंड, यूएसए और स्वीडन की कंपनियों ने भी निवेश किया है। ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ में टेग्ना इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर बन रहा है। लीथियम आयन बैटरी उत्कृष्टता केंद्र भी चल रहा है। अगले पांच साल में विभाग यमुना प्राधिकरण-इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बुंदेलखंड में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर्स और लखनऊ-उन्नाव में चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर की स्थापना करेगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 के तहत विदेशी निवेशकों से 20,490 करोड़ रुपये का निवेश मिला है। जबकि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 के तहत विदेशी निवेशकों ने 300 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव दिया है। पिछले दो साल में यूपीसीडा को सात देशों से 3,200 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। इसमें यूके की तीन कंपनियों ने 1237 करोड़, यूएसए की दो कंपनियों ने 1237 करोड़, फांस से 307 करोड़, इटली से 250 करोड़, कनाडा से सवा सौ करोड़, जर्मनी की दो कंपनियों ने 60 करोड़, साइप्रस से 10 करोड़ रुपये का निवेश है। इससे 8,650 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा।

93 दूतावासों से संपर्क

जीआईएस-23 के लिए 93 दूतावासों, विदेशी औद्योगिक संगठनों, विदेश मंत्रालय और इंवेस्ट इंडिया को पत्र लिखा गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नई नीतियां भी लाई जा रही हैं। इन नीतियों पर विदेशों में होने वाले रोड शो से पहले कैबिनेट में अंतिम मुहर लगाएंगे।